(d) Yes, Sir. Prime Minister of India met with President Sardar Farooq Ahmad Khan Leghari of Pakistan as well as with Prime Minister Begum Khaleda Zia of Bangladesh and discussed matters of mutual interest.

निर्यातोन्मुखी खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्वीकृति

7120. **श्री आस मोहम्मद:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति को उदार बनाए जाने के पश्चात् आज तक शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक स्थापित करने हेतु कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने एककों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और कितने एककों में आज तक कार्य आरंभ नहीं हो पाया है; और

(ग) 31 जनवरी, 1995 तक इन एककों ने कुल कितने मूल्य का निर्यात किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जुलाई, 1991 में औद्योगिक नीति को उदार बनाए जाने से लेकर अब तक प्रसंस्कृत खाद्य मछली प्रसंस्करण तथा गहन समुद्री मत्स्यन समेत समन्वित एक्वाकल्चर संबंधी 459 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनका ब्यौरा विवरण पर दिया गया है। (नीचे देखिये)।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार 41 एककों ने काम करना शुरू कर दिया है। बहरहाल, एक परियोजना को लागू करने में आमतौर पर 2-3 वर्ष लग जाते हैं।

(ग) एकक-वार निर्यात आंकड़े इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

जुलाई, 1991 से मार्च, 1995 तक मंजूर किए गए 100 प्रतिशत निर्यान्तोमुखी यूनिटों का ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य	संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	106
2.	असम	–
3.	बिहार	1
4.	गुजरात	26
5.	हरियाणा	35
6.	हिमाचल प्रदेश	5
7.	कर्नाटक	24
8.	करेल	28
9.	मध्य प्रदेश	3
10.	उड़ीसा	5
11.	पंजाब	6
12.	राजस्थान	19
13.	तमिलनाडु	37
14.	उत्तर प्रदेश	24
15.	पश्चिम बंगाल	11
16.	मेघालय	1
17.	महाराष्ट्र	91
18.	गोवा	5
19.	पांडिचेरी	2
20.	अन्डमान निकाबार	4
21.	दादर तथा नगर हवेली	2
22.	त्रिपुरा	1
23.	भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र/स्थान का उल्लेख नहीं किया गया है।	23
	योग:	459

संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण एकक

7121. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का कोई विवरण है;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे उद्योगों की सही संख्या के अभाव में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की विकास संरचना किस प्रकार से तैयार की जाती है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य और अन्य मांसाहारी सामग्री का निर्यात

7122. **श्री गोपाल सिंह जी. सोलंकी:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के मेडक जिले में किसी संस्थान को मत्स्य और अन्य मांसाहारी सामग्री का निर्यात करने हेतु निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को ऐसे निर्यात से प्रति वर्ष कितनी विदेशी पूंजी की आय होने की संभावना है;

(घ) क्या उपरोक्त संस्थान ने राज्य सरकार की सहायता से ऐसा उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ङ) मंत्रालय को न तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही उसने मेढ़क जिले में किसी संस्थान को मत्स्य और अन्य मांसाहारी सामग्री का निर्यात करने हेतु निर्यातोन्मुखी उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी है।

मध्य प्रदेश में तिलहन संयंत्रों का विस्तार

7123. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सहकारी तिलहन संघ के मुरैना और छिन्दवाड़ा संयंत्रों के विस्तारीकरण के प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर कोई उचित कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल में मध्य प्रदेश सरकार से इस मंत्रालय में या नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जिसका इस विषय से संबंध है, में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

Proposals submitted by FICCI

7124. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to a news-item published in the Hindustan Times dated thd 24th April, 1995 captioned "FICCI plans to boost capital market" with a view to increasing market capitalisation broadening the base of capital market and development of debt market;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) what recommendations were made, decisions taken and proposals submitted by FICCI to Government at its workshop on development of capital market held in Bombay and the 27th April, 1995?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) This Ministry has not received any representation from FICCI in this regard.

Development of fruit and vegetable processing industries

7125. SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to expand fruit and vegetable processing industries during the Eighth Five Year Plan period; and

(b) if so, the details of steps taken to remove regional imbalances in the growth of these units?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) and (b) Yes, Sir. With a view to encourage larger capacity creation for increased processing of fruits and vegetables, including in rural & backward areas, the government have declared most food processing industries, including fruits & vegetable processing industries, as a high priority area and have allowed automatic approval for foreign investment upto 51% to bring in attendant benefits of technology, market access, etc. The Government have also abolished excise duties on all processed fruits and vegetables products and have provided several fiscal reliefs on the capital goods used in this industry. In addition, the Ministry of Food Processing Industries has been implementing various developmental Plan Schemes for promotion of fruit and vegetable processing industries. Besides provision of various incentives by the Central & State Governments for backward areas, Ministry's Plan schemes envisage higher level of assistance for projects in North Eastern States, Hilly & backward areas. Government is encouraging entrepreneours to set up industries in the non-urban & backward areas and is actively promoting the concept of establishment of backward linkages through contract farming. In addition, Government is assisting setting up of food processing training centres to train up the entrepreneours for setting up small processing units in the rural areas. Besides this, the National Horticulture Board,